



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2013/ पौष 3, 1935

No. 304]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2013/PAUSA 3, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2013

**विषय : सुरक्षा कारणों और सरकारी प्रापण में प्रापण हेतु घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को प्राथमिकता**

**सं. 33(3)/2013-आईपीएचडब्ल्यू.**— इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटीवाई) द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं. 8(78)/2010-आईपीएचडब्ल्यू- के जरिए अधिसूचित खरीद में घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को प्राथमिकता देने के लिए नीति के अधिक्रमण में भारत सरकार ने अपने प्रयोग के लिए न कि वाणिज्यिक बिक्री के लिए अथवा न ही वाणिज्यिक बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग के लिए घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए निम्नलिखित नीति बनाई है।

**2.1 विस्तार**

2.1.1 यह नीति व्यावसायिक पुनर्बिक्री की दृष्टि से अथवा व्यावसायिक बिक्री के लिए वस्तुओं में इस्तेमाल की दृष्टि से न होकर सरकारी प्रायोजन से किए गए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के क्रय के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों (रक्षा मंत्रालय के सिवाय) तथा उनकी एजेंसियों के लिए लागू होगी। यह केन्द्रीय रूप से प्रायोजित सभी योजनाओं तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों के अंतर्गत किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के क्रय के लिए भी लागू होगी। पैरा 2.2 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक मंत्रालय/विभाग यह विनिर्दिष्ट करेगा कि क्षेत्र विशेष के घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (उत्पादों) को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे जेनरिक उत्पाद जिनकी खरीद सभी क्षेत्रों में की जाती है जैसे कम्प्यूटर, संचार उपकरण आदि को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/दूर संचार विभाग, जैसा भी मामला होगा, द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

2.1.2 घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (उत्पादों) को प्राथमिकता देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (उत्पादों) से की जाने वाली खरीद का प्रतिशत विनिर्दिष्ट किया जाएगा जो उस इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (उत्पादों) के कुल खरीद मूल्य के 30% से कम नहीं होगा। इसके अलावा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता कितनी होगी जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अपेक्षित गुणवत्ता को पूरा करता है अथवा नहीं। हालांकि यह विनिर्देश नीचे पैरा 2.3 में दिए गए घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की जेनरिक परिभाषा से नीचे नहीं होना चाहिए।

**2.2 शासन तंत्र**

2.2.1 सरकारी खरीद के संदर्भ में नीति के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण द्विचरणीय शासन व्यवस्था द्वारा किया जाएगा।

**चरण 1:** इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय आयोजना और निगरानी परिषद (एनपीएमसी-ईपी) होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

सचिव, डीआईटीवाई ..... अध्यक्ष  
 सचिव, डीओटी या उनके प्रतिनिधि  
 सचिव, व्यय विभाग या उनके प्रतिनिधि  
 सचिव, डीआईपीपी या उनके प्रतिनिधि  
 नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (उत्पादों) को अधिसूचित करने का प्रस्ताव करने वाले मंत्रालय/विभाग के सचिव या उनके प्रतिनिधि  
 महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी)  
 संयुक्त सचिव, डीआईटीवाई – सदस्य-संयोजक

2.2.2 एनपीएमसी-ईपी का अधिदेश निम्नानुसार होगा :

- क. नीति के अंतर्गत अधिसूचित करने के लिए चिह्नित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के संदर्भ में 10 वर्ष के लिए रोड मैप तैयार करना ।
- ख. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी की जाने वाली प्रस्तावित अधिसूचनाओं का अनुमोदन
- ग. नीति के कार्यान्वयन की निगरानी
- घ. शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करना

2.2.3 **चरण 2:** संबंधित मंत्रालय/विभाग एनपीएमसी-ईपी के अनुमोदन के आधार पर सरकारी प्रयोग के लिए खरीदे जा रहे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए आवश्यक अनुपालन आवश्यकताओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिसूचित करेंगे ।

2.2.4 10 फरवरी, 2012 को अधिसूचित पूर्ववर्ती नीति के अंतर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देशों/अधिसूचनाओं की इस नीति के आधार पर एनपीएमसी-ईपी द्वारा समीक्षा की जाएगी । पूर्ववर्ती नीति के अंतर्गत जारी की गई सरकारी खरीद के लिए अधिसूचनाएं तब तक जारी रहेंगी जब तक की संशोधित नीति के अंतर्गत इनकी समीक्षा नहीं की जाती है ।

2.3 **घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद :** घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण उन कंपनियों द्वारा किया जाता है जो भारत में पंजीकृत और स्थापित हैं तथा भारत में विनिर्माण में संलग्न हैं, और इनमें संविदा निर्माता शामिल होंगे, किन्तु इस परिभाषा से ट्रेडरों को अलग कर दिया गया है । ये इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद घरेलू विनिर्माताओं से बिल ऑफ मटीरियल (बीओएम) के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रेडिड घरेलू मूल्यवर्धन को पूरा करेंगे ।

घरेलू विनिर्माता (बीओएम) के संदर्भ में प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन	वर्ष
25%	1 वर्ष
30%	2 वर्ष
35%	3 वर्ष
40%	4 वर्ष
45%	5 वर्ष

## 2.4 घरेलू मूल्य वृद्धि

2.4.1 घरेलू मूल्य-वृद्धि का प्रशित =  $\frac{\text{घरेलू बीओएम} \times 100}{\text{कुल बीओएम}}$

2.4.2 घरेलू विनिर्माण से प्राप्त की गई सामग्री के बिल (घरेलू) बीओएम की गणना प्रत्येक उत्पाद के लिए उपलब्ध डेटा के आधार पर निम्नलिखित पद्धतियों में किसी एक पद्धति के आधार पर की जाए ।

- (क) सभी इनपुट सामग्री जिनसे उत्पाद तैयार होगा कि लागत का योग (केवल उन्हें जिनके लिए क्रेडिट/छूट का लाभ लिया जा सकता है, को छोड़कर सभी इनपुट की खरीद पर लगाए गए शुल्कों और करों सहित) जिनका आयात प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी घरेलू व्यापारी (ट्रेडर) या किसी मध्यस्थ द्वारा नहीं किया गया है ।
- (ख) उत्पाद का एक्स-फैक्टरी मूल्य से कर पश्चात लाभ को घटाकर और उसमें से उत्पाद के उत्पादन में इनपुट के रूप में प्रयुक्त आयातित बीओएम (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष) के योग को घटाकर (केवल उन्हें जिनके लिए क्रेडिट/को छोड़कर सभी इनपुट की खरीद पर लगे गए शुल्कों और करों सहित) छूट का लाभ लिया जा सकता है, को घटाया जाए ।
- (ग) बाजार मूल्य से उत्पादन पश्चात माल-भाड़ा, बीमा और अन्य रख-रखाव लागत को घटाया जाए, उसमें से कर पश्चात लाभ, फिर वारंटी लागत को घटाया जाए, उसमें से उत्पाद के उत्पादन में इनपुट सामग्री के रूप में प्रयुक्त आयाति सामग्री के बिल के योग (केवल उन्हें, जिनके लिए

क्रेडिट/छूट का लाभ लिया जा सकता है, को छोड़कर सभी इनपुट की खरीद पर लगाए गए शुल्कों और करों सहित) को घटाया जाए, फिर उसमें से बिक्री और विपणन व्यय को घटाया जाए।

2.4.3 सामग्री के कुल बिल (कुल बीओएम) की गणना उपलब्ध डाटा के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पद्धति के अनुसार की जाए।

- क) ऐसी सभी इनपुट सामग्री जिनसे उत्पाद तैयार होगा की लागतों का योग/उन्हें, जिनके लिए क्रेडिट/छूट का लाभ लिया जा सकता है, को छोड़कर सभी इनपुट की खरीद पर लगाए गए शुल्कों और करों सहित)
- ख) उत्पाद के फैक्टरी के बाहर मूल्य से कर पश्चात लाभ को घटाकर उसमें से वारंटी लागतों को घटाया जाए।
- ग) बाजार मूल्य से उत्पादन पश्चात मालभाड़ा, बीमा और अन्य रख-रखाव लागतों को घटाया जाए, उसमें से कर पश्चात लाभ को घटाया जाए, उसमें से वारंटी लागतों को घटाया जाए और फिर बिक्री तथा विपणन व्यय को घटाया जाए।

3. **पात्रता :** भारत में पंजीकृत और भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण में संलग्न सभी कंपनियां इस नीति के तहत विचार हेतु पात्र हैं।

4. **प्रापण :** प्रापण एजेंसियां घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के प्रापण के उस निर्दिष्ट प्रतिशत की आवश्यकता पूरी करने के अधीन अपनी प्रापण प्रक्रियाओं का पालन करेंगी।

4.1 वार्षिक आवश्यकताओं और अन्य ऐसी प्रापण प्रथाओं का योग, जो इस नीति के कार्यान्वयन की सुविधा देती हैं, प्रापण एजेंसियों द्वारा अपनाई जाएं।

4.2 सरकार के मंत्रालयों / विभागों या उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एजेंसियों द्वारा प्रापण।

4.2.1 जहां घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का प्रापण इस नीति के तहत एक सरकारी मंत्रालय /विभाग या इसकी एजेंसी द्वारा किया जाता है तो यह प्रापण एल1 मूल्य के मिलान और निविदा की तकनीकी विशिष्टियों की संतुष्टि के अधीन होगा।

4.2.2 सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एजेंसियों द्वारा प्रापण के तहत, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के प्रापण के लिए निविदा में सामान्य तौर पर निर्दिष्ट किया जाएगा कि प्रापण मूल्य का निर्दिष्ट हिस्सा एल1 के साथ मिलान के अधीन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अल्पतम तकनीकी रूप से योग्य पाए गए घरेलू विनिर्माता को सौंपा जाएगा, यदि उक्त निविदाकार उपलब्ध है। शेष एल1 को सौंपा जाएगा चाहे वह एक घरेलू निर्माता है या नहीं। यदि एल-1 दरें किसी घरेलू विनिर्माता द्वारा उद्धृत की जाती हैं तो संपूर्णमात्रा के लिए आदेश ऐसे घरेलू विनिर्माता को दिया जाएगा, बशर्त कि वह आदेश को विभाजित करने से संबंधित निविदा की अन्य शर्तें, यदि कोई हैं को पूरा करता हो।

4.2.3 यह अनिवार्य नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के प्रापण की प्रत्येक निविदा को विभाजित किया जाए। यदि एक निविदा को विभाजित नहीं किया जा सकता तो इसका कारण यह है कि या तो प्रापण की इकाई छोटी है या इसका कोई तकनीकी कारण है या उत्पाद के लिए कोई घरेलू विनिर्माता उपलब्ध नहीं है। प्रापण एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि घरेलू स्तर पर विनिर्मित उत्पादों से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की निर्दिष्ट सीमा के प्रापण की वार्षिक आवश्यकता अन्य निविदाओं में उपयुक्त वृद्धि द्वारा पूरी की जा सकती है।

4.2.4 निविदा की शर्तों में सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है और ये पूर्व अनुभव की प्रतिबंधात्मक अनिवार्य आवश्यकताओं के अधीन नहीं हैं। जबकि प्रापण करने वाले विभाग / एजेंसियों को उक्त शर्तों में शामिल किया जाए, जिसे घरेलू विनिर्माता की उत्पादन क्षमता और उत्पाद गुणवत्ता की संतुष्टि के लिए अनिवार्य पाया जाए।

## 5. अनुपालन

5.1 विक्रेता द्वारा घरेलू मूल्यवर्धन की घोषणा के लिए एक उपयुक्त स्वयं प्रमाणन प्रणाली संकल्पित की जाए। इस प्रणाली में मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) दूर संचार इंजीनियरिंग केन्द्र (टीईसी) (दूरसंचार उत्पादों के लिए) द्वारा और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/दूर संचार विभाग द्वारा प्रत्यायित अन्य परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा जांच करने की सुविधा होनी चाहिए। गलत घोषणा करने के मामलों में उपयुक्त दण्ड अधिरोपित किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए एसटीक्यूसी को मजबूत बनाया जाएगा।

5.2 प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी प्रापण एजेंसियों से प्रतिवर्ष नीति के अनुपालन की सीमा और गैर अनुपालन के कारण की घोषणा प्राप्त करेगा।

5.3 प्रत्येक विभाग/मंत्रालय नीति के तहत अनुपालन के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन/निरुत्साहन प्रदान कर सकता है।

6. **इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद :** एक प्रश्न के मामले में कि क्या प्राप्त किया जा रहा मद इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है जिसे प्रस्तावित नीति में शामिल किया जाना है, तो यह मामला **स्पष्टीकरण** के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भेजा जाएगा।

7. **समय अवधि :** यह नीति आधिकारिक राजपत्र में अपनी अधिसूचना की तिथि से 10 वर्ष के लिए वैध होगी। नीति की नियमित समय अंतराल पर समीक्षा की जाएगी।

8. **दिशानिर्देश :** प्रस्तावित नीति के प्रचालन हेतु विस्तृत दिशानिर्देशों में विक्रेताओं और प्रापण एजेंसियों द्वारा स्वयं प्रमाणन की विधियां बताई जाएंगी और नीति की अधिसूचना के बाद इन्हें जारी किया जाएगा।

9. परिशिष्ट में प्रारूपिक प्रापण के कुछ परिदृश्य बताए गए हैं।

डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव

## प्रारूपिक प्रापण परिदृश्यों के कुछ उदाहरण

## उदाहरण 1

## 1 लाख लैपटॉप का प्रापण

एक सरकारी परियोजना के तहत 1,00,000 लैपटॉप के प्रापण का आशय है। प्रस्तावित नीति के मानक को पूरा करने के लिए उन्होंने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विनिर्माता से 30,000 लैपटॉप प्राप्त करने हैं। निविदा दस्तावेज में प्रापण मूल्य के 30% के संदर्भ में एल1 मूल्य का मिलान करते हुए और निविदा की तकनीकी विशिष्टियां पूरी करते हुए घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मान लें कि इसमें पांच निविदाएं हैं। डीएम को घरेलू विनिर्माता और एनडीएम को गैर घरेलू विनिर्माता मानें।

**प्रकरण 1 :** वाणिज्यिक निविदाओं को खोलने के बाद स्थिति इस प्रकार है एल1: डीएम1, एल 2: एनडीएम 1, एल 3: एनडीएम 2, एल 4: एनडीएम 3 और एल 5: डीएम 2, तो संपूर्ण कार्य डीएम 1 विक्रेता को दिया जाएगा।

**प्रकरण 2क:** वाणिज्यिक निविदाओं को खोलने के बाद स्थिति इस प्रकार है एल1: एनडीएम 1, एल 2: एनडीएम 2, एल 3: एनडीएम 3, एल 4: डीएम 1 और एल 5: डीएम 2। एनडीएम 1 को एल 1 के रूप में योग्य पाया गया और डीएम1 न्यूनतम बोली लगाने वाला घरेलू विनिर्माता है। इसके बाद एनडीएम 1 को प्रापण मूल्य का 70% मूल्य के लिए और क्रय आदेश की 30% मात्रा के लिए आदेश डीएम 1 को दिया जाएगा, बशर्ते कि बाद वाले बोलीदाता की दरें एल1 के सामान हों।

**प्रकरण 2ख:** यदि डीएम 1 एल 1 के मूल्य पर निविदा कार्य लेने से मना करता है तो डीएम 2 को एल 1 मूल्य पर आपूर्ति करने के लिए आदेश दिया जाना चाहिए।

**प्रकरण 3:** वाणिज्यिक निविदाओं को खोलने के बाद स्थिति इस प्रकार है एल 1: एनडीएम 1, एल 2: एनडीएम 2, एल 3: एनडीएम 3, एल 4: एनडीएम 4 और एल 5: एनडीएम 5। इस मामले में कोई घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्माता उपलब्ध नहीं है अतः यह पूरा क्रयदेश एनडीएम 1 को दिया जाएगा।

## उदाहरण 2

## सुपर कम्प्यूटर का प्रापण

प्रापण एजेंसी 50 करोड़ रु. की निर्धारित विशिष्टि के साथ सुपर कम्प्यूटर का प्रापण करने की इच्छुक है। आदेश को दो पक्षकारों के बीच नहीं बांटा जा सकता है। प्रापण एजेंसी 70:30 मानक लागू करने में सक्षम नहीं है। अतः इस निविदा के मामले में यह नीति लागू नहीं की जा सकती है। इसलिए कथित एजेंसी द्वारा घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए 15 करोड़ रु. (पूर्ववर्ती निविदा मूल्य का 30%) का अतिरिक्त मूल्य प्रदान किया जाना चाहिए।

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

## (Department of Electronics and Information Technology)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23<sup>rd</sup> December, 2013

**Subject: Preference to domestically manufactured electronic products in Government procurement**

**No. 33(3)/2013-IPHW.**—In supersession of the policy for providing preference to domestically manufactured electronic goods in procurement, notified vide the Department of Electronics and Information Technology (DeitY) Notification No. 8(78)/2010-IPHW dated 10 February 2012, the Government of India has laid down the following policy for providing preference to domestically manufactured electronic products in Government procurement for its own use and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale.

**2.1 Scope**

2.1.1 The policy will be applicable to all Ministries/Departments (except Ministry of Defence) and their agencies for electronic products purchased for Governmental purposes and not with a view to commercial resale or with a view to use in goods for commercial sale. This would also be applicable for procurement of electronic products made under all Centrally Sponsored Schemes and grants made by Central Government. Subject to the provisions of para 2.2 each Ministry/ Department would notify the sector specific electronic product(s) for which preference would be accorded to domestically manufactured electronic product(s). Generic products, which are procured across sectors, such as, computers, communication equipment etc., would be notified by the Departments of Electronics and Information Technology/Telecommunications, as the case may be.

2.1.2 The notification issued by each Ministry/ Department for providing preference to domestically manufactured electronic product(s) would specify the percentage of procurement to be made from domestically manufactured electronic product(s), which shall not be less than 30% of the total procurement value of that electronic product(s). Further each Ministry/ Department would also specify the domestic value addition requirement which the electronic product should satisfy for the product to qualify as domestically manufactured electronic product. However, such specification should not be below the generic definition of domestically manufactured electronic products provided in para 2.3 below.

## 2.2 Governance Mechanism

2.2.1 A two-tiered governance mechanism shall be established to oversee the implementation of the policy.

**Tier 1:** There shall be a National Planning and Monitoring Council for Electronics Products (NPMC-EP) comprising of the following:

- i. Secretary, DeitY ..... Chairman
- ii. Secretary, Department of Telecommunications (DoT) or representative
- iii. Secretary, Department of Expenditure or representative
- iv. Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), or representative
- v. Secretary of Ministry/ Department proposing to notify electronic product(s) under the Policy, or representative
- vi. Director General, Directorate General of Supplies & Disposals (DGS&D)
- vii. Joint Secretary, DeitY – Member-Convener

2.2.2 The mandate of the NPMC-EP shall be as follows:

- a. Design a 10-year road map for electronic products identified for notification under the policy.
- b. Approval of notifications proposed to be issued by Ministries / Departments of Government of India
- c. Monitoring the implementation of the policy
- d. Establishing a Grievance Redressal System

2.2.3 **Tier 2:** Line Ministries/ Departments will notify electronic products together with the necessary compliance requirements for electronic products being procured for Government use, based on the approval of NPMC-EP.

2.2.4 The notifications/ guidelines issued thus far, under the earlier policy notified on 10th February 2012, shall be reviewed by the NPMC-EP, based on this policy. The notifications for Government procurement issued under earlier policy will continue till these are reviewed under the revised policy.

**2.3 Domestically Manufactured Electronic Products:** The Domestically Manufactured Electronic Products are products manufactured by companies registered in India and engaged in manufacture in India and including Contract Manufacturers, but excluding traders. The electronic products to be notified under this policy shall meet the following graded domestic value-addition in terms of Bill of Material (BOM) from domestic manufacturers.

Percentage domestic value addition in terms of BOM of domestic manufacturers	Year
25%	Year 1
30%	Year 2
35%	Year 3
40%	Year 4
45%	Year 5

## 2.4 Domestic Value Addition

2.4.1 Percentage of domestic value-addition =  $\frac{\text{Domestic BOM} \times 100}{\text{Total-BOM}}$

2.4.2 Bill of Material sourced from domestic manufacturers (Domestic BOM) may be calculated based on one of the following methodologies depending on the data available for each product.

- a. sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken) which have not been imported directly or through a domestic trader or an intermediary.
- b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax minus sum of imported Bill of Material used (directly or indirectly) as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken) minus warranty costs.
- c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax minus warranty costs minus sum of Imported Bill of Material used as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken) minus sales and marketing expenses.

2.4.3 Total Bill of Material (Total-BOM) may be calculated based on one of the following methodologies depending on data available.

- a. sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken).
- b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax, minus warranty costs.
- c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax, minus warranty costs minus sales and marketing expenses.

**3. Eligibility:** All companies registered in India and engaged in manufacture of electronic products in India are eligible for consideration under the policy.

**4. Procurement:** The procuring agencies shall follow their own procurement procedures, subject to meeting the requirement that specified percentage of procurement shall be of domestically manufactured electronic products.

4.1 Aggregation of annual requirements and such other procurement practices, which facilitate the implementation of this policy, may be adopted by procuring agencies.

4.2 Procurement by Government Ministry/ Department or agencies under their administrative control

4.2.1 Wherever the domestically manufactured electronic products are procured under this policy by a Government Ministry/ Department or an agency thereof, such procurement shall be subject to matching of L1 price and on satisfying technical specifications of the tender.

4.2.2 For procurement by Government Ministries/Departments and agencies under their administrative control, the tender for procuring electronic products would normally specify that specified percentage of the procurement value would be awarded to the lowest-priced technically qualified domestic manufacturer of electronic products, subject to matching with L1, if such bidders are available. The remaining will be awarded to L1, irrespective of whether he is a domestic manufacturer or not. In case L1 is quoted by a domestic manufacturer, the entire order quantity will be awarded to such domestic manufacturer, subject to the other conditions of the tender, if any, relating to splitting of the order.

4.2.3 It is not necessary that each tender for the procurement of electronic product is split. If a tender cannot be split, either because the unit of procurement is small or because of technical reasons, or because no domestic manufacturer is available for the product, the procuring agency may ensure that the annual requirement of procuring the specified extent of electronic products from domestically manufactured products is achieved through suitable enhancements in other tenders.

4.2.4 The tender conditions would ensure that domestically manufactured electronic products are encouraged and are not subject to restrictive mandatory requirement of prior experience. However, procuring Department/ Agency may incorporate such stipulations as may be considered necessary to satisfy themselves of the security, production capability and product quality of the domestic manufacturer.

## 5. Compliance

5.1 A suitable self-certification system would be devised to declare domestic value addition by the vendor. The system would also provide for checks by Standardization, Testing and Quality Certification (STQC)/ Telecommunications Engineering Centre (TEC) (for telecom products) and other testing laboratories or technical auditors accredited by the Department of Electronics and Information Technology/ Department of

Telecommunications for the purpose. In cases of false declaration of domestic value addition, suitable penalties will be imposed.

5.2 Each Ministry/ Department shall annually obtain a declaration indicating the extent of compliance to the policy and reasons for non-compliance thereof from all procuring agencies under its administrative control.

5.3 Individual Ministries/ Departments may provide for suitable incentives/ disincentives for compliance of the policy.

**6. Electronic products:** In case of a question whether an item being procured is an electronic product to be covered under the proposed policy, the matter would be referred to the Department of Electronics and Information Technology for clarification.

**7. Time period:** The policy will be valid for 10 years from the date of its notification. The policy will be reviewed at regular intervals of time.

**8. Guidelines:** Detailed guidelines shall be issued for operationalizing the policy which would, *inter alia*, provide for modalities of self-certification by the vendor and the procuring agencies.

9. Some examples of typical procurement scenarios are illustrated in Appendix.

Dr. AJAY KUMAR, Jt. Secy.

## Appendix

### EXAMPLES OF TYPICAL PROCUREMENT SCENARIOS

#### Example 1

##### Procurement of 1 lakh Laptops

Under a Government project, it is intended to procure 100,000 laptops, notified under the policy. In order to fulfill the norm of the proposed policy, they have to procure 30,000 laptops (30%) from domestic manufacturer. The bid documents should specifically provide preference to domestically manufactured electronic products in terms of 30% of procurement value subject to matching of L1 price and on satisfying technical specifications of the tender. Suppose there are five bids. Consider DM as Domestic Manufacturer and NDM as Non Domestic Manufacturer.

**Case 1:** After opening of commercial bids, position is like L1: DM1, L2: NDM1, L3: NDM2, L4: NDM3 and L5: DM2. Then the entire quantity shall be awarded to DM1.

**Case 2A:** After opening of commercial bids, position is like L1: NDM1, L2: NDM2, L3: NDM3, L4: DM1 and L5: DM2. NDM1 qualifies as L1, and DM1 is the lowest-priced domestic manufacturer. Then NDM1 shall be given purchase order for 70% and 30% of the purchase order shall be given to DM1, subject to the later matching the L1 price.

**Case 2B:** If DM1 declines to undertake the tendered work at L1 price, DM2 should be given the offer to supply the 30% at L1 prices.

**Case 3:** After opening of commercial bids, position is like L1: NDM1, L2: NDM2, L3: NDM3, L4: NDM4 and L5: NDM5. In this case, no domestic electronic product manufacturer is available; hence the full order will be awarded to NDM1.

#### Example 2

##### Procurement of Super Computer

Procuring agency desires to procure a Super Computer with prescribed specification for Rs. 50 crore. The order cannot be split between two parties. The procuring agency is not able to apply 70:30 norm. Hence this policy cannot be implemented in this tender. Therefore, in subsequent procurement of electronic products by the said agency, it should reserve an additional value of Rs. 15 crore (30% of the earlier tender) for domestic manufactured electronic products.